योजना का सार

टीबी-मुक्त भारत बनाने हेतु भारत की प्रतिबद्धता

भूमिका

- भारत टीबी का सर्वाधिक भार वहन करने वाले देशों में से एक है। केंद्र और राज्य सरकारें सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 2030 के तहत वैश्विक लक्ष्य से पाँच साल पहले ही 2025 तक इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

टीबी की वैश्विक स्थिति

- WHO के अनुसार, विश्व में लगभग 1.8 बिलियन लोग (वैश्विक आबादी का लगभग 1/4) टीबी से संक्रमित हैं।
- प्रत्येक वर्ष लगभग 13 लाख बच्चे टीबी से बीमार पड़ते हैं। यह दुनिया भर में मौतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख संक्रामक कारणों में से एक है।
- विश्व के, 87% टीबी मामलों का भार उच्च संक्रमण वाले 30 देशों पर है। इनमें से वैश्विक मामलों का कुल 2/3 हिस्सा आठ देशों में पाया गया।
- कुल वैश्विक मामलों में 27% भारत से आते हैं इसके बाद इंडोनेशिया (10%)] चीन (7.1%)] फिलीपींस (7.0%)] पाकिस्तान (5.7%)] नाइजीरिया (4.5%)] बांग्लादेश (3.6%) और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (3.0%) का स्थान आता है।

टीबी को प्रभावित करने वाले कारक

- टीबी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कारकों द्वारा गहनता से प्रभावित होता है।

- WHO के अनुसार, वैश्विक स्तर पर टीबी के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख कारक हैं-
- कुपोषण
  - एच.आई.वी. संक्रमण
  - मद्य सेवन
  - धूम्रपान
  - मधुमेह
- हालाँकि, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें भिन्नताएँ हैं। उदाहरण के लिए, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली शहरी आबादी में इसका विस्तार अधिक देखा गया है।

भारत की प्रगति

- WHO ने वर्ष 2015-2022 तक क्षयरोग की घटनाओं में 16% और इसके कारण होने वाली मृत्यु दर में 18% की कमी लाने में भारत की प्रगति की सराहना की है।
- भारत में टीबी गिरावट की गति वैश्विक टीबी घटनाओं में कमी की गति से लगभग दोगुनी है, जो कि 8.7% है।
- भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी-मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है।

टीबी-मुक्त भारत के लिए प्रमुख पहलें

- वर्ष 2025 तक टीबी से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं -
- ***राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम:*** केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) को लागू किया जा रहा है-

- टीबी रोगियों का शीघ्र निदान, गुणवत्तापूर्ण दवाओं और उपचार पद्धतियों के साथ शीघ्र उपचार।
- निजी क्षेत्र में देखभाल चाहने वाले मरीज़ों से जुड़ना।
- रोकथाम कार्यनीतियों में उच्च जोखिम/संवेदनशील आबादी में संपर्क का पता लगाना।
- वायुजनित संक्रमण नियंत्रण
- सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए बहु- क्षेत्रीय प्रतिक्रिया।
- **प्रधानमंत्री टीबी-मुक्त भारत अभियान:** टीबी के विरुद्ध लड़ाई को मिशन मोड दृष्टिकोण देने के लिए इस अभियान को सितंबर, 2022 में शुरू किया गया था।

उद्देश्य :

- वर्ष 2025 तक टीबी के संबंध में एस.डी.जी. लक्ष्य को पूरा करने के लिए गतिविधियों और पहलों को तैयार करना।
- इस पहल ने सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक 'जन आंदोलन' के रूप में एक-साथ लाकर टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाया।
- इसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों का भी लाभ प्राप्त हुआ।
- **नि-क्षय मित्र:** इस पहल के अंतर्गत टीबी रोगियों को उनके ठीक होने की यात्रा में मदद करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के स्वयंसेवक 'मित्र' की तरह कार्य करते हैं।
- नि-क्षय मित्र वे व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियाँ, धार्मिक संगठन, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल और अन्य हो सकते हैं, जो टीबी रोगियों को पोषण सहायता, पोषण-संबंधी पूरक, अतिरिक्त जाँच और व्यावसायिक

सहायता के रूप में कम-से-कम छह महीने या अधिकतम 3 साल तक की अवधि के लिए सहायता करने के लिए सहमति देते हैं।

- **सक्रिय मामलों का पता लगाने संबंधी अभियान:** टीबी के 'गुमनाम रोगियों' तक पहुँचने के लिए राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम की कार्यनीतिक योजना के हिस्से के रूप में उच्च जोखिम वाले समूहों में राष्ट्रीय समुदाय-आधारित 'सक्रिय मामलों का पता लगाने संबंधी' अभियान शुरू किया।
- इस कार्यक्रम के तहत, संवेदनशील आबादी के बीच टीबी के मामलों की घर-घर जाकर सक्रिय जाँच की जाती है।
- इस गतिविधि के परिणामस्वरूप, इसकी शुरुआत से अब तक लगभग 3 लाख अतिरिक्त टीबी मामलों का निदान हुआ है।
- **टीबी-मुक्त पंचायत अभियान:** टीबी-मुक्त पंचायतों का उद्देश्य पंचायतों को टीबी से जुड़ी समस्याओं की सीमा और परिमाण से अवगत कराने और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाना, पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करना और उनके योगदान की सराहना करना है।
- **नई टीबी-रोधी दवाओं का प्रभाव:** सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में अल्पकालीन, सुरक्षित ओरल बेडाक्विलिन युक्त दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार शुरू किए गए हैं।
- **नि-क्षय पोषण योजना:** टीबी के लिए कुपोषण एक महत्त्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में पाया गया है जिसका टीबी रोगियों के स्वास्थ्य लाभ पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- इस प्रबल सह-संबंध को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में 'नि-क्षय पोषण योजना' (NPY) की शुरुआत की, जिसके तहत टीबी रोगियों को उपचार

की पूरी अवधि के दौरान पोषण-समर्थन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में 500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।

- **बुनियादी ढाँचे का विस्तार:** सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाने में नैदानिक आधारभूत ढाँचे (डायग्नोस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) ने अहम भूमिका निभाई है। ठोस प्रयासों के माध्यम से टीबी प्रयोगशाला सेवाओं के बुनियादी ढाँचे का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- पिछले 9 वर्षों में डिजिग्नेटिड माइक्रोस्कोपी केंद्रों (DMC) में 80% की वृद्धि हुई है।
- साथ ही, अब तक 6,196 नई आणविक नैदानिक प्रयोगशालाएँ (Molecular Diagnostic Laboratories) स्थापित की गई हैं।
- दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार केंद्रों की संख्या वर्ष 2014 में 127 से बढ़कर वर्ष 2022 में 792 हो गई है।
- **उपराष्ट्रीय रोगमुक्त प्रमाणीकरण:** राज्य/संघ शासित प्रदेशों/ज़िला स्तर पर टीबी महामारी की प्रवृत्तियों की निगरानी करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामुदायिक स्तर के सर्वेक्षण पद्धति (Inverse Sampling Method) के माध्यम से रोग का अनुमान लगाने और निजी क्षेत्र में दवा बिक्री के आँकड़ों पर नज़र रखने तथा कार्यक्रम के लिए कम प्राप्त सूचना के स्तर को मापने की एक नई पहल शुरू की है।
- इस पद्धति के माध्यम से टीबी रोग के राज्य/संघ शासित प्रदेशों/ज़िला स्तर के अनुमान निकाले जाते हैं और उन्हें वर्ष 2015 की आधार रेखा के आधार पर मापा जाता है।

निष्कर्ष

- टीबी से निपटने के लिए समय सीमा और जवाबदेही संरचनाओं के साथ एक व्यापक-आधारित कार्य-योजना की आवश्यकता है जिसकी समुदायों, विभिन्न हितधारकों और भागीदारों को शामिल करते हुए परिश्रमपूर्वक निगरानी की जाए।

भारत के गुमनाम स्वतं=ता सेनानी

संदर्भ

- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न भागों से ऐसे अनेक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो इतिहास में कम चर्चित रहे। हालाँकि उनकी नि:स्वार्थ गतिविधियाँ और बलिदान राष्ट्र के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए एक कालातीत आघ्ह्वान के साथ प्रतिध्वनित होते हैं।

रानी अब्बक्का : संप्रभुता और न्याय की अडिग संरक्षक

- 13oha-18oha सदी के मध्य कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र के अंतर्गत उल्लाला और पुट्टीगे में चौटा लोगों का शासन था जो मातृसत्तात्मक (अलियाकट्टू) का पालन करते थे। इस शाखा के संबंध में पाँच 'अब्ब्क्का' रानियों का उल्लेख मिलता है। संभवत: 'अब्बक्का' किसी एक रानी के नाम के बजाय एक उपाधि या पारिवारिक नाम था।
- पुर्तगाली और इतावली अभिलेखों से दो अब्बक्का रानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिन्होंने 16oha सदी के मध्य से 17oha के प्रारंभ तक उल्लाला पर शासन किया। इनकी स्पष्ट रूप से माँ और बेटी के रूप में पहचान की गई है।

- 'अब्बक्का' रानियाँ जैन धर्म का पालन करती थीं, लेकिन उनके पास सभी धर्मों के लोगों की एक एकीकृत सेना और प्रशासनिक व्यवस्था थी।
- बड़ी अब्बक्का ने वर्ष 1554-88 के बीच पुर्तगालियों के विरुद्ध तीन महत्त्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी हालाँकि वह इन युद्धों में हार गई।
- छोटी अब्बक्का ने वर्ष 1618 में पुर्तगाली सेना को निर्णायक रूप से हराया और इस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश बनाने से रोका।
- अब्बक्का रानियों ने पुर्तगालियों के लिए एक मज़बूत खतरा उत्पन्न किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में उनकी विस्तार की नीति को दबाने की कोशिश की। विदेशी वर्चस्व के खिलाफ रानी अब्बक्का का प्रतिरोध और अपने लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है।

मुलु मानेक और जोधा मानेक

- गुजरात के ओखामंडल के वाघेर योद्धा वर्ष 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश में शासन के खिलाफ प्रतिरोध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्ष 1857 के विद्रोह में मुलु मानेक और जोधा मानेक के नेतृत्व में वाघेरों ने ओखा से ब्रिटिश शासन को खदेड़ दिया। मार्च, 1858 तक वे बेट द्वारका किले में पहुँच गए थे। जोधा मानेक द्वारका के राजा बन गए और जुलाई 1859 तक राजा बने रहे।
- हालाँकि बाद में पुन: अंग्रेज़ों ने वहाँ कब्ज़ा जमा लिया था, लेकिन अपनी पराजय हो जाने के बावजूद जोधा और मुलु लगातार गोरिल्ला युद्ध अर्थात् छापामार युद्ध चलाते रहे।

रणछोड़लाल छोटेलाल : आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी

- अंग्रेज़ों के भारत में शासन का नतीजा यह हुआ कि हमारी परंपरागत शिल्पों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया तथा इस स्थिति का विस्तृत वर्णन दादाभाई नौरोजी ने भारत की संपदा को इंग्लैंड ले जाने के बारे में अपने लेखों में किया है।
- गुजरात ऐतिहासिक काल से ही उद्यमशील रहा है। वर्ष 1823 में जन्में रणछोड़लाल छोटेलाल के नेतृत्व में गुजरात में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को गति और बढ़ावा मिला।
- इन्होंने वर्ष 1859 में स्वयं की 'अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड' खोली।
- उद्योगों के साथ ही रणछोड़लाल ने अहमदाबाद नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में अपने योगदान से वहाँ के नागरिक जीवन को सुधारने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- विदेशी सरकार के प्रति विद्रोह के साथ ही उन्होंने सीवेज प्रणाली और नल से पानी की व्यवस्था सुधारकर साफ-सफाई में क्रांतिकारी बदलाव किया तथा इन प्रयासों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली।
- रणछोड़लाल ने भारतीय कपास पर लगने वाली प्रतिपूरक शुल्क (Countervailing Duty) का वर्ष 1896 में विरोध किया और वर्ष 1884-85 के प्रतिबंधात्मक फैक्ट्री एक्ट का भी विरोध किया।
- इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई तथा लड़कियों की शिक्षा और गरीबी मिटाने के समर्थन में अहमदाबाद में आयोजित छठे वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति की अध्यक्षता की।

गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत

- दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में स्थानीय शासकों और प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट करने में गोविंद गुरु ने अथक प्रयास किए।
- ब्रिटिश सेना को चुनौती देने के उद्देश्य से गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर, 1913 को गुजरात-राजस्थान सीमा के नज़दीक मानगढ़ पहाड़ी में एकत्रित करीब डेढ़ हज़ार भील लोगों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी के साथ गोली चला दी।
- बाद में गोविंद गुरु पकड़ लिए गए और उन्हें मौत की सज़ा दी गई जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया।
- उदयपुर में वर्ष 1886 में जन्मे मोतीलाल तेजावत ने मसालों के अपने कारोबार में आदिवासियों के शोषण को देखकर उनके अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प किया।
- उन्होंने भीलों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की। गांधीजी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेकर भीलों ने तेजावत की अगुवाई में नाजायज़ कर देने से मना कर दिया और ब्रिटिश शासकों के यहाँ बंधुवा मज़दूर बनने से भी इनकार कर दिया।

झावेरचंद मेघाणी

- गुजरात में चोटिला में वर्ष 1896 में जन्मे झावेरचंद मेघाणी को महात्मा गांधी ने 'राष्ट्रीय शायर' का नाम दिया।
- युवावस्था में ही वे एक गुजराती अखबार के संपादक बन गए थे और गांधीजी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खासकर छोलेरा में वे बहुत सक्रिय रहें।

- उनकी शायरी के संग्रह 'सिंधुवाडो' में साहस और बहादुरी के विषय पर पूरा ज़ोर दिया गया है। मेघाणी के प्रभावी और सशक्त लेखन से ब्रिटिश सरकार को खतरे का एहसास हुआ और उन्हें अवैध ढंग से गिरफ्तार कर लिया।

वसंत और रज़ाब : घृणा के दौर में सांप्रदायिक सद्भाव की गाथा

- 1 जुलाई, 1946 को अहमदाबाद में रथयात्रा के दौरान दंगे भड़कने से नगर में अराजकता का माहौल के बीच दो युवा मित्र- वसंत राव हेगिश्ते और रज़ाब अली लखानी ने लोगों की जान बचाने के लिए पूरी बहादुरी से काम किया।
- बढ़ती हिंसा के बावजूद वसंत और रज़ाब ने बेखौफ होकर दंगाइयों के सामने डटकर उन्हें अपनी कार्रवाई रोकने को कहा।
- हिंसा के दौरान ये दोनों युवक भी शहीद हो गए जो असल में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे।
- अहमदाबाद आज भी उनके बलिदान का सम्मान करता है और घृणा तथा हिंसा के माहौल में साहस और एकता का प्रतीक मानकर उन्हें आदरपूर्वक याद करता है।

हंसा मेहता

- वर्ष 1897 में सूरत में जन्मे हंसा मेहता ने सामाजिक रूढ़ियों की अनदेखी करते हुए दर्शनशास्त्र में स्नातक उपाधि अर्जित की जबकि 20oha सदी के आरंभिक काल में महिला शिक्षा का चलन बहुत ही कम था।
- 1920 के दशक में उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का तब अवसर मिला जब उन्हें भारत में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1930 में हंसा ने महिलाओं से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की अपील दोहराई।
- वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के ऐतिहासिक सम्मेलन में शामिल हुई दो महिला-प्रतिनिधियों में हंसा मेहता भी थीं। उन्होंने मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा की समग्र भाषा के लिए ज़ोरदार वकालत की थी।

- भारत की संविधान सभा में शामिल 15 महिला प्रतिनिधियों में शामिल हंसा मेहता ने मुख्य भूमिका निभाई थी और भारतीय महिलाओं की ओर से 15 अगस्त, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया था।
- संविधान सभा में अपने कार्यकाल में उन्होंने समान नागरिक संहिता और स्त्री-पुरुष समानता जैसे अहम मुद्दों पर आवाज़ बुलंद की तथा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार और महिला सशक्तीकरण की दिशा में अग्रणी प्रयासों की परंपरा बरकरार रखी।

कोयापल्ली केलप्पन

- कोयापल्ली केलप्पन (के. केलप्पन) एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे।
- इन्हें 'केरल गांधी' के नाम से भी जाना जाता है।
- केलप्पन वर्ष 1925 में प्रसिद्ध वायकोम सत्याग्रह और वर्ष 1932 में गुरुवायुर सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्ति थे, दोनों ही सत्याग्रहों में अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की गई थी।
- ये केरल से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले पहले सत्याग्रही थे।
- 18 सितंबर, 1932 को इन्होंने अस्पृश्यता समाप्त होने तक गुरुवायुर मंदिर के सामने आमरण अनशन करने के अपने निर्णय की घोषणा की। केलप्पन की 12 दिवसीय भूख हड़ताल ने श्री गुरुवायुर मंदिर को सभी जातियों के हिंदू भक्तों के लिए खोल दिया गया।
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन्हें 9 अगस्त, 1942 को अन्य महत्त्वपूर्ण कमांडरों के साथ गिरफ्तार किया गया और 28 जून, 1945 तक जेल में रहे।

गोमधर कोंवर : असम के पहले शहीद

- अंग्रेज़ों द्वारा असम पर कब्ज़ा करने के 2 साल बाद, शाही अहोम वंश के सदस्य गोमधर कोंवर ने पहली प्रतिरोध मंडली का गठन किया।

- अक्तूबर, 1828 की शुरुआत में, गोमधर ने एक सभा बुलाकर अंग्रेज़ों को कर न देने की अपील की और विद्रोही गतिविधियों की शुरुआत की। नवंबर में उन्हें औपचारिक रूप से जोरहाट के पास बास्सा में राजा घोषित किया।
- जल्द ही उन्हें और उनके साथियों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में इस सज़ा को निर्वासन में 7 साल के कारावास में बदल दिया गया और उन्हें बंगाल (अब बांग्लादेश में) की रंगपुर जेल में भेज दिया गया। यह माना गया कि जेल में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई।
- तदनुसार, गोमधर कोंवर को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में शहादत पाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है।

मूंगरी : पहली शहीद महिला

- स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहते हुए अपनी जान गंवाने वाली पहली महिला मूंगरी शराब विरोधी अभियान से जुड़ी रहीं। उन्होंने विशेष रूप से असम के चाय बागान श्रमिकों से शराब की लत छोड़ने की अपील की।
- यह ब्रिटिश बागान मालिक ही थे जिन्होंने मज़दूरों में शराब पीने की आदत डाली थी। अभियान में शामिल होने के कुछ दिनों के भीतर ही अज्ञात हमलावरों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी।

अरुणाचल प्रदेश के बोम सिंगफो

- बोम सिंगफो ने असम प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर लगभग 400 लोगों की एक सेना का गठन किया था और रंगपुर (शिवसागर) में ब्रिटिश स्टेशन पर हमला किया था।
- बोम सिंगफो सहित इस हमले में शामिल छह नेताओं को जल्द ही पकड़ लिया गया। उन पर रंगपुर में मुकदमा चलाकर उन्हें 'देशद्रोह का दोषी' ठहराया गया तथा उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई।
- बाद में, बोम सिंगफो सहित चार लोगों की मौत की सज़ा को असम से 14 साल के निर्वासन में बदल दिया गया और कठोर कारावास के लिए ढाका

जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

- जेल में रहते हुए बोम सिंगफो की बीमारी से मृत्यु हो गई, इस प्रकार वे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों से शहीद होने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

का फान नोनग्लैट : एक साहसी महिला

- मेघालय के खासी समाज के मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक होने के कारण, उसकी महिलाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई थी।
- ऐसी ही एक बहादुर महिला- का फान नोनग्लैट थीं, जिनकी साहस और देशभक्ति की कहानी खासी लोगों की पीढ़ियों द्वारा लगातार लोककथा के रूप में सुनाई जाती है।

रोपुइलियानी : मिज़ोरम की एक बहादुर महिला

- रोपुइलियानी का जन्म वर्ष 1828 में हुआ था। इन्होंने लुशाई पहाड़ी के डेनलुंग गाँव की मुखिया के रूप में अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र से होकर सड़क बनाने से मना कर दिया।
- उन्होंने सहायक या मुफ्त श्रम की ब्रिटिश मांग का भी कड़ा विरोध किया।
- रोपुइलियानी और उनके बेटे, लालथुआमा को 9 अगस्त, 1893 को गिरफ्तार कर लिया गया। लुंगलेई जेल में बंद रोपुइलियानी ने समझौता करने से इनकार कर दिया और इस तरह उन्हें अपने बेटे के साथ 8 अप्रैल, 1894 को रंगमती निर्वासित कर दिया गया। बाद में उन्हें चटगाँव जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

सचिंद्र लाल सिंह : त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानी

- त्रिपुरा में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के संदर्भ में सचिंद्र लाल का नाम उल्लेखनीय है सचिंद्र ने विक्टोरिया कॉलेज, कोमिला (अब बांग्लादेश में) में शिक्षा प्राप्त की। सचिंद्र लाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे।

- सचिंद्र लाल सिंह बंगाल के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के सहयोगी थे, जिन्होंने 18 अप्रैल, 1930 को प्रसिद्ध चटगाँव शस्त्रागार पर छापे की योजना बनाई थी।
- सचिंद्र लाल सिंह ने वर्ष 1939-42 के रियांग विद्रोह का हिस्सा बने और रतनमणि रियांग एवं रियांग विद्रोह के अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम किया। औपनिवेशिक काल के दौरान ये लगभग 14 साल जेल में रहें।
- भारत की स्वतंत्रता और त्रिपुरा रियासत के भारतीय संघ में विलय के बाद, जुलाई 1963 से नवंबर 1971 तक त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री बने।

सेल्यूलर जेल

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य शहर पोर्टब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल का निर्माण वर्ष 1896-1906 के बीच हुआ था।
- इसका निर्माण पोर्ट ब्लेयर मे कैदियों को मज़दूरों के रूप मे तैनात करके किया गया था।
- 'देशद्रोही' या 'अराजकतावादी' के रूप में वर्गीकृत राजनीतिक कैदियों को यहाँ निरुद्ध किया जाता था।
- उन्हे श्रेणी 'डी' (खतरनाक) या 'पी.आई.' (स्थायी रूप से कैद) बैज दिए जाते थे।
- वर्ष 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के राजनीतिक कैदियों के लिए आम माफी की घोषणा की गई और सेल्यूलर जेल को बंद किया गया।

जंबुद्वीप उद्घोषणा

- 16 जून, 1801 दक्षिण भारत के तिरुचापल्ली के स्थानीय शासक चिन्ना मरुधु पांडियार द्वारा सभी देशभक्त नागरिकों से यूरोपीय उपनिवेशवादियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की उद्घोषणा की गई।
- भारतीय इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भारतीय शासक ने ऐसी उद्घोषणा जारी की हो।

स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं व सिनेमा का योगदान

संदर्भ

- स्वतंत्रता आंदोलनों में साहित्य और सिनेमा की भूमिका को अक्सर कम करके आंका जाता है और कई बार तो इसे नज़रंदाज भी कर दिया जाता है। हालाँकि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ साहित्यिक रचनाओं ने मौखिक या लिखित रूप में सामाजिक आंदोलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं इस दौरान जनता की भावनाओं को जागृत करने एवं औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने वाले एक शक्तिशाली माध्यम के रूप सिनेमा की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही।

भारतीय भाषाओं का योगदान

- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी भाषाओं और पूरे देश में साहित्यिक हमले से घबराकर, हतोत्साहित होकर अंग्रेज़ों ने उन किताबों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया जिनमें थोड़ी-सी भी राष्ट्रवादी या देशभक्ति की भावना थी।
- यह ऐसा समय था जब मुख्यधारा की भाषाओं में प्रकाशित पत्रिकाओं और उनके लेखकों को आंदोलन में योगदान जारी रखने में मदद की और स्वतंत्रता सेनानियों को अपना संदेश आम जनता तक पहुँचाने में सक्षम बनाया।
- तत्कालीन सरकार ने सभी भाषाओं की पत्रिकाओं पर नकेल कसनी शुरू की, तो इससे भूमिगत पत्रिकाओं और पुस्तकों का उदय शुरू हुआ।
- कई भाषाओं में पत्रिकाओं और दैनिकों ने व्यंग्य और धुंधली भाषा का इस्तेमाल किया, ताकि विदेशी शासक आसानी से संदेश न समझ सकें जबकि स्थानीय लोग इसे आसानी से समझ सकते थे और सूचना या कहानी को फैला सकते थे।

- उस दौर की पत्रकारिता और प्रिंट माध्यम ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
- 19oha और 20oha सदी के दौरान भारत की लगभग सभी भाषाओं के महान विचारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे-
- **मराठी:** बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विष्णु वामन शिरवाडकर, खांडेकर आदि।
- **कन्नड़:** शिवराम कारंत, कुवेम्पु, सिद्धवनहल्ली कृष्ण शर्मा आदि।
- **तेलुगु:** गुरजाड़ा अप्पाराव, मंगीपुडी वेंकटराय शर्मा, तुम्माला सीताराममूर्ति, रायाप्रोलु सुब्बाराव, चेरुकुवड़ा वेंकट रामैया, दुव्वुरी रामिरेड्डी, लक्ष्मी नारायण, करुणाश्री, गरिमेला सत्यनारायण आदि।
- **तमिल:** सुब्रमण्यम भारती, भारती दासन, नामक्कल कविनगर, वी.ओ. चिदंबरम, पी. जीवनंदम, वी.वी.एस. अबयर, राजाजी आदि।
- **गुजराती:** महात्मा गांधी, गोपबंधु दास, गोवर्धन राम त्रिपाठी, नरहरि द्वारकादास पारीख, उमाशंकर जोशी, सुंदरजी बेटाई, सुंदरम, नरसिंह राव, मनसुखलाल झावेरी, बादरायण आदि।
- **मलयालम:** वल्लथोल मेनन, वैकोम मुहम्मद बशीर, सहोदरन अबयप्पन आदि।
- **बंगाली:** रंगलाल बंद्योपाध्याय, मधुसूदन दत्ता, दीनबंधु मित्रा, गिरीश चंद्र घोष, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रबींद्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, काज़ी नज़रूल इस्लाम आदि।
- **हिंदी:** मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, बेचन शर्मा उग्र और गोविंद वल्लभ पंत, मुंशी प्रेमचंद आदि लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

सिनेमा का योगदान

- 20oha सदी की शुरुआत में सिनेमा एक लोकप्रिय माध्यम बनकर उभरा। भारतीय सिनेमा को अब 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता की भावनाओं को जागृत करने, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने वाले एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- अपने शुरुआती दौर में इसने देशभक्ति, वीरता और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह जैसे विषयों को दर्शाया।
- दादा साहब फाल्के की 'राजा हरिश्चंद्र' (1913)] कांजीभाई राठौड़ की 'भक्त विदुर' (1921) और एच.एम. रेड्डी की 'भक्त प्रह्लाद' (1931) जैसी फिल्मों ने नैतिक साहस और धार्मिकता को दर्शाया जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की भावनाओं को प्रदर्शित करती थी।
- सिनेमा ने भारत और विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि फिल्म उद्योग ने शुरू में मुंबई में ही जड़ें जमाई थी। मराठी सिनेमा ने अपनी फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रवादी मूल्यों और आदर्शों का सक्रिय रूप से प्रचार किया।
- 'संत तुकाराम' (1936) और 'दुनिया ना माने' (1937) जैसी फिल्मों ने सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का गुणगान किया।
- फिल्मों ने शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई आदि जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में दर्शाया।

निष्कर्ष

- इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागृति का एक प्रभावपूर्ण साधन था। इसने जनमत को आकार देने, प्रतिरोध की भावना को पोषित करने और अंतत: भारत के वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।